आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीकरण का लघु उद्योगों पर प्रभाव

1295. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीकरण का तेलियों द्वारा तेल निकालने तथा कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे गांवों के लघु और कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और उनकी संख्या दिन-प्रति दिन घटती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने में तथा उनका इतना विकास करने में कि वे समय के साथ-साथ अपने काम को बदल सकें, खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितनी सफलता मिली है और इस क्षेत्र में उनकी अब तक क्या भूमिका रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी नहीं । उत्पादन के समान क्षेत्रों में आधुनिक बड़े उद्योगों के विस्तार के फलस्वरूप, ग्रामोद्योगों में लगे पारम्परिक कारीगरों का विस्थापन रोकने के विचार से सरकार के० वी० आई० को रियायती वित्त, वित्तीय रियायतें तथा प्रौद्योगिक उन्नयन, उत्पादन में विविधीकरण तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने एवं बिक्री बढ़ाने के रूप में सहायता दे रही है । नये एवं गैर-पारम्परिक कच्चे-माल का पता लगाने, उत्पादों के रूप तथा क्वालिटी में सुधार करने तथा कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने एवं श्रमिकों को विस्थापित न होने देने के साथ ही काम करने सुविधाजनक बनाने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम भी शुरु किया है । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अनेक उन्नत तथा नये उपकरणों का सूत्रपात किया है । खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की सूची में शामिल ग्रामीण उद्योगों के अंतर्गत रोजगार निरन्तर बढ़ रहा है । 1982-83 से पिछले तीन वर्षों में ग्रामोद्योग क्षेत्र में घानी तेल तथा ग्रामीण कुम्हारी उद्योग में भी निम्नलिखित रूप में रोजगार बढ़ा है :—

(लाख व्यक्ति)

	घानी तेल	ग्रामीण कुम्हारी
1982–83	0.60	2.22
1983–84	0.65	2.37
1984–85	0.68	2.52

Law Commission recommendations for speedy and inexpensive justice

1296. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Law Commission favoured grassroots justice which would be both speedy and inexpensive as reported in the 'Indian Express' of 30th October, 1986, and if so, what steps have been taken in this direction; and

(b) whether the Law Commission is also in favour of setting up of independent judicial forum at the level of High Courts instead of present set up of Tribunals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) The Law Commission has been entrusted with the study of judicial reforms and has furnished its 114th Report on Gram Nyayalaya and 115th Report on Tax Courts. Action is being taken to lay the copies of the Report on the Table of Parliament.

After the report is laid on the Table of Parliament, an indepth study of the report will be made and a decision will be taken as to whether, and if so, on what lines, the recommendations contained in the Report are to be implemented by legislation.